



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 27 सितम्बर, 2004/5 आश्विन, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 25 सितम्बर, 2004

संख्या 7-2/2000 ई० एल० एन०.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई० डी०/2004 न्यायिक-II (उप), दिनांक 18 सितम्बर, 2004, जिसमें 37—गुलेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन-2004 के लिए आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान-पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से

मनीषा नन्दा,  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

## भारत निर्वाचन आयोग,

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

संख्या 3/4/आई0 डी0/2004/न्यायिक-11 (उप) ।

तारीख : 18 सितम्बर, 2004.

## आदेश

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान बनाया जाए ; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 निर्वाचन आयोग को निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और मतदान के समय उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटोग्राफ सहित फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निर्देश देने का अधिकार देता है ; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 त (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किया गया है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपने पहचान पत्र जारी करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने और मना करने पर मतपत्र देने और वोट डालने से उन्हें मना किया जा सकता है ; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों का सम्मिलित और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहां राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान पत्र जारी किया गया है वहां दोनों का ही साथ-साथ प्रयोग में लाया जाना है ; और

5. यतः निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था ; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र कार्यक्रम जारी करने के लिए कार्यान्वयन शुरू किया गया है, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन-क्षेत्रों ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों जिनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी हो या वे निर्वाचन क्षेत्र के बाहर चले गए हो और उन्होंने मतदाता फोटो पहचान-पत्र कहीं और से प्राप्त कर लिए हों, को ध्यान में रखते हुए पहचान-पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों और इलाकों में चक्कों द्वारा दोहराते हुए अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचकों को पहचान-पत्र जारी किए हैं । और

7. यतः, जनवरी-मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचनों, अप्रैल-मई, 2001 में हुए केरल, तमिलानडू, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी की विधान सभाओं के लिए हुए निर्वाचनों, और वर्ष 2002 में हुए मणिपुर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा और गुजरात और गत वर्ष में हुए हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और दिल्ली विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों

और इस वर्ष के शुरू में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और सिक्किम की विधान सभाओं तथा लोक सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचनों और इस बीच हुए बहुत से उप-निर्वाचनों में आयोग ने यह निर्देश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, मतदान करते समय अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन शेष निर्वाचकों जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी वनात कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके ; और

8. अतः उच्चतम न्यायालय को, आर० डी० भंडारी एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में आयोग के उपरोक्त निर्देश से अवगत करवाया गया और उच्चतम न्यायालय ने मतदाता फोटो पहचान-पत्र सम्बन्धी सभी याचिकाएं 17 अगस्त, 2000 को खारिज कर दी ; और

9. यतः, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्रमशः 2000 की रिट अर्जी सं० 2598, 2601 और 2637 तथा 2001 की रिट अर्जी सं० 3772 और 2001 की रिट अर्जी सं० 5235, 2002 की रिट अर्जी सं० 294 तथा 2002 की रिट अर्जी सं० 5401 में आयोग के निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान से संबंधित उपर्युक्त निर्देशों को क्रमशः मान्य ठहराया है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस० एल० पी० नं० 3820-21/2002 पर एक अन्तरिम आदेश पारित किया जिसमें यह निर्देश दिया कि जनवरी-फरवरी 2002 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में आयोग के आदेश लागू किए जाएं ।

10. यतः, अब, सभी सम्बन्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है, कि उत्तर प्रदेश राज्य में 65—मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में 21—मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 1—बीदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश में 220—सिद्धीपेट तथा 213—असफनगर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोवा में 40—पोइनतिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 29—भनवाद 103—खेदब्रह्मा (अनुसूचित जनजाति) 138—बोसंद, 164—व्यारा तथा 179—धर्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 37—गुलेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर में 18—कौन्याऊजम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 52—तौहटा, तथा 93—बालाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में 6—तेनिंग (अनुसूचित जनजाति), 26—अंग्लेनडेन (अनुसूचित जनजाति), तथा 45—तेहोक (अनुसूचित जनजाति) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 41—कपूरथला, तथा 45—गढ़शंकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 58—बहरोड़, तथा 199—मेड़ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 69—अहिरौर (अनुसूचित जाति), 120—मल्कीपुर, 124—सिद्धौर (अनुसूचित जाति), 144—मुजेहना, 220—सैदपुर, 235—मरियाह, 252—करचना, 261—इलाहाबाद पश्चिम, 356—अतरौली, 359—इगलास, 372—गाजियाबाद और 394—बघरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरांचल में 45—द्वाराहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 141—श्यामपुकर 142—जोराबगान और 153—इन्टाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्य क्षेत्र में 15—राजौरी गार्डन तथा 70—बलजीत नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए 18 सितम्बर, 2004 को अधिसूचित (उत्तरांचल में 45—द्वाराहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन 18 सितम्बर, 2004 को अधिसूचित) चालू उप-निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने के लिए आते समय और अपने मतधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा ।

11. निर्वाचन आयोग इस बात को दोहराते हुए यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि चालू उप-निर्वाचन में निर्वाचकों को निर्वाचन आयोग के प्राधिकार के अधीन जारी निर्वाचक पहचान-पत्र के माध्यम से मतदान केन्द्र पर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी । हालांकि उन्हें मतदान के उद्देश्य के लिए मतदाता पहचान-पत्र का प्रत्येक प्रारम्भिक चरणों में है, आयोग इस मामले में पर्याप्त सतर्कता के रूप में उन शेष निर्वाचकों को चालू

उप-निर्वाचन में मत देने की अनुमति देगा, जिन्होंने मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, बशर्ते उनकी पहचान पीओसीन अधिकारी या दूसरे मतदान अधिकारी, जिसे पीओसीन अधिकारी ने प्राधिकृत किया है, कि संतुष्टि में अन्यथा स्थापित हो जाती है, उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे निर्वाचकों की पहचान सिद्ध करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं :—

- (i) पासपोर्ट
- (ii) ड्राईविंग लाइसेंस
- (iii) आयकर पहचान पत्र (पीओएन)
- (iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र
- (v) बैंक/किसान/डकघर पासबुक (1-9-2004 को या उससे पूर्व खोला गया खाता)
- (vi) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान द्वारा 1 सितम्बर, 2004 को या उससे पूर्व जारी छात्र-पहचान-पत्र।
- (vii) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि
- (viii) 1 सितम्बर, 2004 को या उससे पूर्व जारी राशन कार्ड
- (ix) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 1 सितम्बर, 2004 को या उससे पूर्व जारी अ० जा०/अ० ज० जा०/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र
- (x) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश।
- (xi) रेलवे पहचान पत्र
- (xii) स्वतन्त्रता सेनानी पहचान-पत्र
- (xiii) शस्त्र लाइसेंस
- (xiv) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 1 सितम्बर, 2004 को या उससे पूर्व जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र।

12. पहचान के लिए उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेज उन शेष निर्वाचकों, जिन्हें मतदाता पहचान-पत्र सप्लाई तो किए गए किन्तु जिन्हें वे ऐसे कारणों से प्रस्तुत करने में असफल हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं, पर भी लागू होंगे।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर गिनाए गए कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, को परिवार के दूसरे सदस्यों के पहचान के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती है।

आदेश से,

हस्ताक्षरित/-  
(के० एन० विल्फ्रेड),  
सचिव।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

*Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi-110 001.*

**No. 3/4/ID/2004/J.S.II/(BYE)**

*Dated 18th September, 2004.*

**ORDER**

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electoral Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling ; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electoral Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost ; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2)(b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electoral Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960 , the electors shall produce their Electoral Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards may result in the denial of permission to vote ; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electoral Identity Card, where provided by the Election Commission at State Cost, and that both are to be used together ; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electoral Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme ; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Manipur, Madhya Pradesh, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, West Bengal, Bihar, Karnataka and NCT of Delhi have issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors, many of whom might have been dead or might have moved out of the constituencies and obtained their Electoral Identity Cards elsewhere ; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March, 2000, and to the Legislative Assemblies of Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Pondicherry in April-May, 2001 and to the Legislative Assemblies of Manipur, Punjab, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Goa and Gujarat held in 2002 and at the Legislative

Assembly elections held in Himachal Pradesh, Meghalaya Nagaland, Tripura, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Mizoram and Delhi last year and at the general election to the House of the People and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa and Sikkim held earlier this year, and at a number of Bye-Elections held in between the Commission had directed that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission ; and

8. Whereas, the Supreme Court was apprised of the direction of the Commission regarding use of EPIC, in *R. D. Bhandari & Others Vs. Election Commission of India & Others*, and the Supreme Court was thereupon pleased to dismiss on 17-8-2000 all petitions relating to the issue of EPICs ; and

9. Whereas, the Andhra Pradesh High Court and Punjab & Haryana High Court, Madras High Court, High Court of Madhya Pradesh and High Court of Karnataka have also upheld the above direction of the Commission regarding compulsory identification of electors, in Writ Petition Nos. 2598, 2601 and 2637 of 2001, Writ Petition No. 3772 of 2000, Writ Petition No. 5235 of 2001, Writ Petition 294 of 2002 and Writ Petition 5401 of 2002 respectively, and the Hon'ble Supreme Court in the interim order passed on in SLP No. 3820-21/2002, directed that the Commission's Order regarding identification of electors at the general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in January-February 2002 would be implemented.

10. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 65—Manipuri Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh, 21—Madhepura Parliamentary Constituency in Bihar, 1—Bidar Parliamentary Constituency in Karnataka, 220—Siddipet and 213—Asafnagar Assembly Constituencies in Andhra Pradesh, 40—Pongu Assembly Constituency in Goa, 29—Bhanvad, 103—Khedbrahma (ST), 138—Borsad, 164—Vyara and 179—Dharampur Assembly Constituencies in Gujarat, 37—Guler Assembly Constituency in Himachal Pradesh, 18—Konthoujam Assembly Constituency in Manipur, 52—Nohata & 93—Balaghat Assembly Constituencies in Madhya Pradesh, 6—Tenning (ST), 26—Anongolenden (ST) and 45—Tehok (ST) Assembly Constituencies in Nagaland, 41—Kapurthala and 45—Garshankar Assembly Constituencies in Punjab, 58—Behror and 199—Merta Assembly Constituencies in Rajasthan, 69—Ahirori (SC), 120—Milkipur, 124—Siddhaur (SC), 144—Mujehna, 220—Saidpur, 235—Mariahu, 252—Karchana, 261—Allahabad West, 356—Atrauli, 359—Iglas, 372—Ghazaiabad and 394—Baghra Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 45—Dwarahat Assembly Constituency in Uttaranchal, 141—Shyanipukur, 142—Jorabagan and 153—Entally Assembly Constituencies in West Bengal and 15—Rajouri Garden and 70—Baljeet Nagar Assembly Constituencies in NCT of Delhi, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current Bye-Elections to the House of the People and Legislative Assemblies from the said constituencies, notified on 15th September, 2004 and 18th September, 2004 (for Bye-Election in 45—Dwarahat Assembly Constituency in Uttaranchal).

11. The Election Commission wishes to make it clear, at the cost of repetition, that the electors at the current Bye-Elections will have to establish their identity at the polling stations by means of the EPICs issued to them under the authority of the Election Commission however, since the use of EPICs for the purpose of voting, is still in its early stages, the Commission, as a matter of abundant caution, will permit the odd electors who have not obtained their EPICs, to vote at the current Bye-Elections, provided their identity is otherwise



established to the satisfaction of the Presiding Officer or such other polling Officer as is authorised by the Presiding Officer in this behalf. For the above purpose they will have to produce some documentary evidence for establishing their identity, and the Commission has prescribed the following alternative documents for establishing the identity of such electors:—

- (i) Passports,
- (ii) Driving Licences,
- (iii) Income Tax Identity (PAN) Cards,
- (iv) Service Identity Cards issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or other Private Industrial Houses,
- (v) Bank/Kisan/Post Office Passbooks (Accounts opened on or before 1st September, 2004,
- (vi) Student Identity Cards issued by Recognised Educational Institutions on or before 1st September, 2004,
- (vii) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds, etc.,
- (viii) Ration Cards issued on or before 1st September, 2004,
- (ix) SC/ST/OBC Certificates issued by competent authority on or before 1st September, 2004,
- (x) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/ Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order,
- (xi) Railway Identification Cards,
- (xii) Freedom Fighter Identity Cards,
- (xiii) Arms Licenses,
- (xiv) Certificate of Physical Handicap by Competent Authority issued on or before 1st September, 2004.

12. The above alternative documents for identification will also apply in respect of such of the odd electors, who have been supplied with Electoral Identity Cards, but are not able to produce them for reasons beyond their control.

13. It is clarified that any document, as enumerated above, which is available only for the Head of Family shall be allowed for the purpose of identification of other members of the family. Similarly, and document in the name of any other member of the family could also be used for identification of other members provided the other members can be identified on the basis of such document.

By order,

Sd/-  
(K. F. WILFRED),  
Secretary.

